स्टेट लेवल को-ऑर्डिनेटर, तेल उद्योग, छत्तीसगढ़
द्वारा
'इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (मार्केटिंग डिवीजन)
'इंडियन ऑयल भवन', राजीव गाँधी मार्ग, (व्ही.आई.पी. रोड)
रविग्राम, तेलीबांधा, रायपुर - 492 006 (छत्तीसगढ़)

STATE LEVEL CO-ORDINATOR, OIL INDUSTRY, CHHATTISGARH
C/o. :
'INDIAN OIL CORPORATION LTD.' (Marketing Division)
'INDIAN OIL BHAVAN', Rajiv Gandhi Marg, (VIP Road)
Ravigram, Telibandha, RAIPUR - 492 006 (Chhattisgarh)
Phone : 0771-4313033, 4313039

Press Release

PSU Oil Marketing Companies maintain steady fuel supply in Chhattisgarh

Raipur, Date:20.04.2026

Public Sector Oil Marketing Companies (IOCL, BPCL and HPCL) have maintained steady and adequate supplies of LPG and automative fuel in Chhattisgarh, despite the ongoing geopolitical volatility.

PSU Oil Marketing Companies (OMC) have prioritised domestic LPG supplies and LPG cylinder delivery continues as normal.

Oil Marketing Companies (OMCs) have maintained uninterrupted LPG supply to households and are currently delivering around 72000 LPG cylinders daily on an industry basis in the state of Chhattisgarh, which is consistent with normal delivery levels prior to the onset of recent geopolitical tensions and in line with the current requirement.

Sufficient bottling capacity exists in the State of Chhattisgarh with 05 (IOC-02, BPC-01 & HPC-02) bottling plants of PSU Oil Marketing Companies. These plants hold adequate stocks, receive inputs as per requirement and are presently meeting full demand of LPG customers in the State through a network of 539 (IOC-268, BPC-112 & HPC-159) distributors. Besides domestic LPG, supply of commercial LPG is also being released as per guidelines to various sectors under close monitoring of Oil Companies and the State Government.

OMCs are also supplying 5 KG Cylinders as a convenient option for those with low gas consumption or who do not have local address proof like Students, Migrant workers, Working young population etc. Camps are also being held by select OMC distributors at industrial clusters like Urla, Siltara, Hathkoj, Tifra, Sirgitti, Pathripali, Bhupdeopur & others in the Chhattisgarh to help such population.

Customers are encouraged to use digital modes such as SMS, Missed Call and IVRS for booking LPG refills. At present, nearly 98% of bookings are received through digital platforms. Deliveries are being carried out with Delivery Authentication Codes (DAC OTP) to ensure cylinders are received by the genuine customers.

The Oil Marketing Companies (OMCs) are actively listening to the concerns shared on social media platforms and remain committed to addressing them promptly. Reports of malpractices by certain

LPG distributors have been noted through social media and customer complaints. To curb black-marketing and hoarding, multiple teams have been deployed by OMCs to conduct surprise inspections of LPG distributorships. Oil Marketing Companies are working closely with State Governments across the country including in Chhattisgarh to prevent malpractices and curb hoarding.

In the State of Chhattisgarh, district authorities have cumulatively carried out 419 raids and lodged 105 FIR's with 3946 cylinders seized till date.

Oil Marketing Companies reassures all LPG customers that supplies remain adequate and there is no shortage of LPG in the country. Customers are advised not to queue at LPG distributorships and to avoid panic booking or stocking of LPG cylinders. They are also urged not to believe in rumours and to rely only on official sources of information. Oil Marketing Companies remain fully committed to ensuring seamless LPG availability, transparency in distribution, and strict enforcement against malpractices.

The OMCs are committed to supplying petrol and diesel in accordance with customers' requirement. As of today, Oil Industry has 2587 Retail Outlets (Petrol Pumps /fuel stations) (IOC-1029, BPC-672, HPC-815) spread across the length and breadth of Chhattisgarh, including 71 Petrol Pumps/Fuel stations operated by private Oil Companies.

With robust storage infrastructure and supply logistics comprising 2 Terminals and 1 bulk POL depots, the state has sufficient storage capacity, and these locations are maintaining adequate stocks of Petrol and Diesel to ensure uninterrupted supplies. Additionally, stocks are being consistently replenished through pipelines and rail wagons, and there is absolutely no concern regarding product availability in the state.

Oil Marketing Companies are currently supplying approximately 5600 KL of Petrol and 9800 KL of Diesel per day in the State of CG which was previously 3800 KL for Petrol and 6500 KL for Diesel per day before this Geopolitical Crisis. There is adequate availability of fuel at Petrol Pumps to meet demand, particularly during the current agricultural season.

The public is advised not to pay attention to rumours of any shortage or engage in panic buying.

All three OMCs are committed to ensuring seamless supply of fuel in the state.

Issued by:

(Nitin Chavan)

Divisional Retail Sales Head (DRSH), Raipur DO, IndianOil

& State Level Coordinator, Chhattisgarh

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

छत्तीसगढ़ में उर्वरकों का सुचारू प्रबंधन: संतुलित पोषक तत्व उपयोग पर सरकार का जोर

राज्य सरकार द्वारा खरीफ-2026 के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, साथ-ही मिट्टी की सेहत सुधारने हेतु 'एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन' (Integrated Nutrient Management) पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहने के बजाय पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग से पैदावार बढ़ाई जा सकती है साथ ही लागत कम करके ज्यादा आमदनी प्राप्त की जा सकती है ।

- खरीफ-2026 में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर भारत सरकार से समन्वय कर रही है | इस वर्ष खरीफ के लिए **15.55 लाख टन** उर्वरक मांग का आँकलन किया गया है तथा 17 अप्रैल तक **8.72 लाख टन** लगभग 56 प्रतिशत का भंडारण करा लिया गया है |
- प्रदेश की सहकारी समितियों से ऋण लेकर खेती करने वाले किसानों को प्राथमिकता से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सहकारी क्षेत्र में 4.83 लाख टन का भंडारण करा लिया गया है |
- कृषि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है की किसानों को उनकी भूमिधारिता के आधार पर अनुशंसित मात्रा में ही उर्वरक का विक्रय हो | इसके लिए विभाग द्वारा नई ऑनलाइन व्यवस्था पर काम किया जा रहा है तथा मई माह से इसे प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है | इस नई प्रणाली में एकीकृत किसान पोर्टल, राजस्व विभाग का भूईयाँ पोर्टल और एग्रीस्टैक पोर्टल को इंटीग्रेट किया जाएगा |
- एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा कई पहल किये गये हैं| विभाग द्वारा हरी खाद के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 22 हजार हे. में प्रदर्शन की योजना तैयार की गई है | हरी खाद ना सिर्फ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है बल्कि इसका बायोमास सड़कर मिट्टी की संरचना मे सुधार भी करता है |

इसी प्रकार, कृषि विभाग नील हरित काई के उपयोग को भी प्रोत्साहित कर रहा है | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य हेतु चिन्हित नील हरित काई के मदर

कल्चर का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों, शासकीय उद्यान रोपणियों एवं शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में इसका वृहद उत्पादन प्रारंभ किया गया है तथा माह मई से इसका कल्चर प्रगतिशील कृषकों को भी उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा ताकि राज्य के बड़े क्षेत्र में उपयोग द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर कर यूरिया के समरूप पोषक तत्व फसल को उपलब्ध कराया जा सके।

- छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अभनपुर में स्थापित जैव उर्वरक संयंत्र में फास्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया (पी.एस.बी.), एजोस्पाइरिलम आदि जैव उर्वरकों का उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा शीघ्र ही किसानों के लिए उपलब्ध होगा | पी.एस.बी. मिट्टी में उपलब्ध फॉस्फोरस को घुलनशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध कराता है तथा एजोस्पाइरिलम वायु में उपलब्ध नाइट्रोजन का धान के खेतों में स्थिरीकरण करता है।
- यूरिया और डीएपी के विकल्प के रूप में नैनो उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है ताकि न्यूनतम कास्त लागत पर प्रति इकाई अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। मैदानी अमले के द्वारा नैनो उर्वरक के प्रभावी उपयोग के संबंध में कृषकों को प्रशिक्षण एवं समझाइश दी जा रही है ।
- कृषि विभाग द्वारा "विकसित कृषि संकल्प अभियान" अंतर्गत संतुलित उर्वरक उपयोग, हरी खाद, नील हरित काई का उपयोग, नैनो उर्वरक आदि के उपयोग विधि, इनके लाभ एवं परिणाम से किसानों को अवगत कराने की तैयारी की जा रही है |
- प्रदेश में उर्वरकों के अवैध भंडारण, अधिक मूल्य पर विक्रय तथा समस्त अन्य गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उड़नदस्ता तथा निरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी निर्देश भी सभी कलेक्टरों को जारी किए जा चुके हैं।
- प्रदेश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा भारत सरकार से सतत् समन्वय किया जा रहा है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री द्वारा उर्वरक उपलब्धता की निरंतर समीक्षा की जा रही है तथा सरकार विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है ।

--00--

प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश में एलपीजी एवं पेट्रोल/डीजल आपूर्ति की अद्यतन स्थिति

दिनांक 28.02.2026 को पश्चिम एशिया संकट प्रारंभ होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा प्रदेश की ईंधन संबंधी आवश्यकताओं की सुगम आपूर्ति हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के नियमित संपर्क में हैं। भारत सरकार द्वारा एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की राज्यों में उपलब्धता, नियमित आपूर्ति की साप्ताहिक समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। भारत सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि देश में एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा आम उपभोक्ताओं में इसे लेकर कोई भ्रम अथवा अफवाह की स्थिति नहीं होनी चाहिए।

प्रदेश में 63.59 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं तथा इन्हें वितरित करने हेतु माह मार्च 2026 में एवं वर्तमान माह अप्रैल 2026 में घरेलू एलपीजी की मांग अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। माह मार्च 2026 में 35,000 टन घरेलू एलपीजी की आवश्यकता के विरूद्ध 35,073 टन (100%) एवं वर्तमान माह अप्रैल में 19 अप्रैल तक 20,619 टन घरेलू एलपीजी राज्य को प्राप्त हुई है तथा राज्य के सभी 4 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। माह मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में भ्रम एवं अफवाह के कारण औसत दैनिक बुकिंग संख्या 74,000 से बढ़कर 1,30,000 तक हो गई थी, जो वर्तमान में घटकर औसतन 64,000 हो गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी की मांग अनुसार आपूर्ति होने से असामान्य बुकिंग में कमी आई है तथा वर्तमान माह अप्रैल 2026 में यह सामान्य स्तर पर आ गई है।

राज्य में कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को वितरित करने हेतु पर्याप्त एलपीजी का स्टॉक उपलब्ध है। माह अप्रैल 2026 में 1533 टन एलपीजी कमर्शियल उपभोक्ताओं हेतु आबंटित की गई है, जिसके विरूद्ध 1745 टन अर्थात 116 प्रतिशत एलपीजी उपलब्ध है एवं 19 अप्रैल 2026 तक 885 टन कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा चुकी है।

प्रदेश में संचालित 2465 पेट्रोल/डीजल पंप में तथा 3 ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त पेट्रोल/डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। माह मार्च 2026 में प्रदेश की मासिक पेट्रोल आवश्यकता 1.01 लाख किलोलीटर के विरूद्ध 1.27 लाख किलोलीटर (126%) एवं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल 2026 तक 77,942 किलोलीटर पेट्रोल की राज्य को प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार मार्च 2026 में प्रदेश की मासिक डीजल आवश्यकता 1.64 लाख किलोलीटर के विरूद्ध 3.00 लाख किलोलीटर (183%) एवं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल 2026 तक 1.17 लाख किलोलीटर डीजल की राज्य को प्राप्ति हुई है। इससे स्पष्ट है कि राज्य में पेट्रोल एवं डीजल की मांग अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है।

प्रदेश में एलपीजी एवं डीजल/पेट्रोल की जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए सभी जिलों आकस्मिक जांच/छापे की कार्यवाही की जा रही है तथा अब तक 419 मारे गये छापों में 3946 सिलेण्डर जब्त किये गये हैं तथा 105 व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य स्तर तथा सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित हैं तथा आम उपभोक्ता से शिकायत प्राप्ति हेतु विभागीय कॉल सेंटर (1800–233–3663) भी संचालित है।